पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल आने वाली है तथा जो गेहूं व चावल FCI गोदामों से बाहर पड़ा हुआ है वह और भी सड़ेगा। हम गरीबों को नहीं देंगे, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में सड़ा हुआ गल्ला भेजेंगे। मैं यह मांग करती हूं कि सरकार एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनाकर तुरंत जांच कराए और जो भी खराब गेहूं है, उसको वापस मंगवाए। इसके साथ ही यह इसकी नीति में पूर्णरूप से सुधार करके हमारे आदिवासी भाई-बहनों को सही गेहूं व चावल दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The entire House associates itself with this Zero Hour mention. ...*(Interruptions)*... The Government will definitely take note of it. The entire House is associated with it. This is the sentiment of the House.

Safe storage of wheat and grains, use of pesticides and resultant spoilage

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated): Hon. Deputy Chairman, Sir, I want to bring to the attention of this august House that the country is sitting on a grain bomb. Due to the grace of God and good monsoons we are going to have a record output of wheat of 82 million tonnes. The storage of grains is the greatest challenge that this country faces. The current stock with the Government is worth Rs.40,000 crores. Extra storage which has been sanctioned is 150 lakh tonnes. Regrettably, only one per cent construction has been completed so far. Last year the wastage was 50,000 tonnes of wheat. But that is the official figure. The quantity actually wasted is significantly more. As a consequence, there is going to be widespread use of pesticides and insecticides to prevent the grain from being eaten by rodents. As the hon. Member has said, the use of pesticides and insecticides is very harmful especially to women and children. I think this is a very serious matter. I urge the Government to bring out a White Paper on the calamity of plenty that this country faces.

I would also like to bring to the attention of the House, through you, Sir, that this year is going to be another record year for the production of fruits and vegetables, up to 40 per cent of which is likely to be wasted. Unless the APMC rules are modified and more investment is invited for storage, distribution and cold storage, we will again have inflationary issues coming up later in the year. This is a very critical issue, Sir. I wish this House would take notice of it and request for a full debate on this issue, especially in a country of plenty where plenty of people do not get access to the foodgrains which are rotting due to poor storage, inadequate storage and inadequate investment. Both the public sector and the private sector must take up this issue on a war footing basis and go in for adequate storage facilities because we have been blessed with good monsoon. In other countries like Russia, China and Australia, the wheat crop has failed. India is in a uniquely fortunate position. Let us not convert that fortune into a calamity. I thank you, Sir.

PROF. M.S. SWAMINATHAN (Nominated): Sir, I associate myself with the issue raised by Dr. Ashok S. Ganguly.

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA (Nominated): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Non-implementation of the recommendations of the Majithia Wage Board for journalists and non-journalists

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका, सदन का और खास तौर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतन को ठीक ढंग से लागू करने के लिए2007 में एक बोर्ड का गठन हुआ था। वेतन बोर्ड ने पूरी बारीकी से काम करके सरकार के समक्ष31.12.2010 को अपनी सिफारिशें दी हैं। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक उन सिफारिशों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पत्रकार और गैर-पत्रकार बंधु agitated हैं। आज उसी संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वेmarch भी कर रहे हैं। महँगाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सब लोगों का वेतन बढ़ा है, यहाँ तक कि हम लोगों का वेतन भी बढ़ा है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो पत्रकार और गैर-पत्रकार हैं, जो media persons हैं, उनके लिए अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बोर्ड की जो सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं, उन्हें अविलम्ब लागू किया जाए, ताकि इस महँगाई के समय मीडिया के लोगों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकेऔर उन्हें सुविधा मिल सके, ताकि उनकी रोजी-रोटी का जो सवाल उठ खड़ा हुआ है, उनमें बड़े पैमाने पर जो agitation हो गया है, उनके मन में जो आक्रोश है, वह शांत हो सके।

इसलिए मैं पुन: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुएयह माँग करता हूँ कि media persons के लिए बोर्ड के माध्यम से जो अनुशंसाएँजो सिफारिशें दी गई है, उन्हें सरकार अविलम्ब लागू करे।धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rudra Narayan Pany, Shri Ali Anwar Ansari and Shri Shantaram Laxman Naik to associate themselves.

श्री रामचन्द्र खूंटिआ (उड़ीसा): महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, मैं राम कृपाल यादव जी के उल्लेख को एसोसिएट करता हूं सब लोग उन्हें एसोसिएट कर रहे हैं*...(व्यवधान)...* सर, हम लोग एक-एक मिनट तो बोलेंगे न? *...(व्यवधान)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, I am going according to the list. I will give you time.

श्री रुद्रनारायण पाणि: उपसभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मजीठिया वेतन बोर्ड जल्दी से जल्दी लागू किया जाए*...(व्यवधान)...* मीडिया कर्मचारी पूरे देश में इस कमर तोड़ महंगाई के कारण